

प्रभारी  
आवपत्र वितरण एकक

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARYभाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYPO-350  
km-30  
Depth-100  
CPB-220

सं. 84]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925

No. 84]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 128(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्तें और पदावधि) नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध आयोग में (अनुसूचित जातियों से संबंधित पदों के सिवाय) अनुसूचित जनजातियों की बाबत ऐसे पदों से है, आंशिक रूप से उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्तें और पदावधि) नियम, 2004 है।

(2) ये संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) “अनुच्छेद” से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है ;

(ख) “अध्यक्ष” से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

- (ग) “आयोग” से अनुच्छेद 338क के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है ;
- (घ) “सदस्य” से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है ;
- (ङ) “अनुसूचित जनजाति” पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 366 के खंड (25) में है ;
- (च) “उपाध्यक्ष” से आयोग का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

3. अर्हताएं— (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जाएंगी जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान दिया है ।

(2) उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) अध्यक्ष की नियुक्ति अनुसूचित जनजातियों के ऐसे प्रतिष्ठित, सामाजिक- राजनैतिक कार्यकर्ताओं में से की जाएगी जो अपने विशिष्ट व्यक्तित्व और निःस्वार्थ सेवा के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के बीच विश्वास पैदा करते हैं ;

(ख) उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से नियुक्ति किए जाएंगे ;

(ग) कम से कम एक अन्य सदस्य महिलाओं में से नियुक्त किया जाएगा ;

4. पदावधि— (1) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसी तारीख से, जिसको वह ऐसा पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य दो पदावधियों से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

5. वेतन और भत्ते— (1) जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, अध्यक्ष भारत सरकार के मंत्रिमंडल सदस्य की पंक्ति का होगा तथा उपाध्यक्ष राज्यमंत्री की पंक्ति का और सदस्य भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के होंगे ।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे, जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय हैं :

परन्तु अध्यक्ष किरायामुक्त आवास का भी हकदार होगा ।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, संसद् या किसी राज्य विधान मंडल का सदस्य है तो वह, यथास्थिति, संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित भत्तों से भिन्न या ऐसे भत्तों से भिन्न यदि कोई हों, किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा जो राज्य के विधान मंडल का कोई सदस्य, राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए निरर्हता के निवारण से संबंधित राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी निरर्हता उपगत किए बिना प्राप्त कर सकेगा ।

**6. स्थायी या अस्थायी रिक्तियों की दशा में व्यवस्था--**(1) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा तब तक किया जाएगा जब तक, यथास्थिति, नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है या विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभाल लेता है ।

(2) यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि उपाध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे अन्य सदस्य द्वारा, जैसा राष्ट्रपति निदेश दे, तब तक किया जाएगा जब तक नया उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है या विद्यमान उपाध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभाल लेता है ।

**7. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध--**

जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है अथवा कोई सेवानिवृत्त सरकारी सेवक है अथवा किसी अन्य संस्था या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त सेवक है और किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त कर रहा है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाता है वहां इन नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय वेतन में से उस पेंशन की

रकम और यदि उसने पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो, पेंशन के उस भाग की रकम कम कर दी जाएगी ।

**8. पदत्याग और हटाया जाना -** (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(2)(क) अध्यक्ष को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर ऐसे न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के खंड (1) के उपखंड (ज) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात् किया गया है कि अध्यक्ष को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए ;

(ख) राष्ट्रपति, अध्यक्ष को, जिसके संबंध में इस उपनियम के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है ;

(ग) खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष :-

(i) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है ; या

(ii) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है ; या

(iii) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है,

तो राष्ट्रपति अध्यक्ष को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा :

परंतु अध्यक्ष को इस खंड के अधीन पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ;

(घ) यदि अध्यक्ष, निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा, उस संविदा या करार से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार के

द्वारा या उसकी ओर से की गई या किया गया है, किसी प्रकार से संपृक्त या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ या उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है तो वह खंड (क) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

(3) राष्ट्रपति, किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष या सदस्य के पद से तभी हटाएगा जब वह व्यक्ति,—

(क) अनुमोचित दिवालिया है ;

(ख) किसी अपराध के लिए जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है ;

(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है ;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ है ;

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति की इजाजत लिए बिना, आयोग की तीन क्रमवर्ती बैठकों से अनुपस्थित रहता है ; या

(च) राष्ट्रपति की राय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है कि उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए हानिकारक होगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस उपनियम के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

561-21/04

[फा. सं. 17014/12/99-टीडीआर]

एस. चटर्जी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th February, 2004

**G.S.R. 128(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 338 A of the Constitution and in partial supersession of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Chairperson, Vice-Chairperson and Members (Conditions of Service and Tenure) Rules, 1990, in so far as they relate to such posts in the Commission with respect to the Scheduled Tribes (except the posts relating to the Scheduled Castes), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement:** - (1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes Chairperson, Vice-Chairperson and Members (Conditions of Service and Tenure) Rules, 2004

(2) They shall come into force on the date of commencement of the Constitution (Eighty-ninth Amendment) Act, 2003.

2. **Definitions:** - In these rules, unless the context otherwise requires:-

- (a) “article” means article of the Constitution;
- (b) “Chairperson” means the Chairperson of the Commission;
- (c) “Commission” means the National Commission for Scheduled Tribes established under article 338 A;
- (d) “Member” means a Member of the Commission;
- (e) the expression “Scheduled Tribes” shall have the meaning assigned to it in clause (25) of article 366;
- (f) “Vice-Chairperson” means the Vice-Chairperson of the Commission.

3. **Qualifications:**- (1) The Chairperson, the Vice-Chairperson and the Members shall be appointed from amongst persons of ability, integrity and standing who have had a record of selfless service to the cause of justice for the Scheduled Tribes.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1)

(a) the Chairperson shall be appointed from amongst eminent socio-political workers belonging to the Scheduled Tribes, who inspire confidence amongst the Scheduled Tribes by their very personality and record of selfless service;

(b) the Vice-Chairperson and other Members out of whom at least two shall be appointed from amongst persons belonging to the Scheduled Tribes;

(c) at least one other Member shall be appointed from amongst women;

4. **Term of Office:-** (1) Save as otherwise provided in these rules, the Chairperson, the Vice-Chairperson and other Members shall hold office for a term of three years from the date on which he/she assumes such office.

(2) The Chairperson, the Vice-Chairperson and other Members shall not be eligible for appointment for more than two terms.

5. **Salaries and allowances -** (1) The Chairperson shall have the rank of a Cabinet Minister and the Vice-Chairperson that of a Minister of State and other Members shall have the rank of the Secretary to Government of India unless otherwise specified.

(2) The Chairperson, the Vice-Chairperson and other Members shall be entitled to such salaries and allowances as are admissible to a Secretary to the Government of India:

Provided that the Chairperson shall also be entitled to a rent free accommodation.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), if the Chairperson, Vice-Chairperson or any other Member is a Member of Parliament, or a State Legislature he/she shall not be entitled to any remuneration other than the allowances, defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or as the case may be, other than the allowances, if any, which a Member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature receive without incurring such disqualification.

6. **Arrangement in case of permanent or temporary vacancies:** (1) If the office of the Chairperson becomes vacant or if the Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until the new Chairperson assumes office or the existing Chairperson resumes his office, as the case may be, be discharged by the Vice-Chairperson.

(2) If the office of the Vice-Chairperson becomes vacant or if the Vice-Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until the new Vice-Chairperson assumes office or the existing Vice-Chairperson resumes his office, be discharged by such other Member as the President may direct.

**7. Special provision for retired persons appointed as Chairperson, Vice-Chairperson and other Members: -** Where any person, being a retired judge of the Supreme Court or of a High Court or a retired government servant or retired servant of any other institution or autonomous body and in receipt of a pension in respect of any previous service, is appointed as the Chairperson, the Vice-Chairperson or a Member, the salary admissible to him under these rules shall be reduced by the amount of that pension and if he had received in lieu of a portion of the pension, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension.

**8. Resignation and Removal: -** (1) The Chairperson, Vice-Chairperson and any other Member, may, by notice in writing under his hand addressed to the President, resign his post.

(2) (a) The Chairperson shall only be removed from his office by order of the President on the ground of misbehavior after the Supreme Court, on reference being made to it by the President, has on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in sub-clause (j) of clause (1) of article 145 of the Constitution, reported that the Chairperson ought on any such ground to be removed.

(b) The President may suspend from office the Chairperson in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under this sub-rule until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(c) Notwithstanding anything in clause (a) the President may by order remove from office the Chairperson if the Chairperson,-

(i) is adjudged as an insolvent; or

(ii) engaged during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(iii) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body:



Provided that the Chairperson shall not be removed under this clause until he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(d) If the Chairperson is or becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or the government of a State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising there from otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of clause (a) be deemed to be guilty of misbehavior.

(3) The President shall remove a person from the office of Vice-Chairperson or Member if that person, -

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the President involves moral turpitude,

(c) is in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body,

(d) refuses to act or becomes incapable of acting,

(e) is without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission, or

(f) in the opinion of the President has so abused the position of Vice-Chairperson or Member as to render that persons' continuance in office detrimental to the interest of the Scheduled Tribes.

Provided that no person shall be removed under this clause until he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

[F. No. 17014/12/99-TDR]

S. CHATTERJEE, Jt. Secy.